



राष्ट्रीय सेमिनार भारत में सार्वजनिक नीति के समसामयिक सन्दर्भ : चुनौतियाँ एवं सम्भावनाएँ

**Present Context of Public Policies in India:
Challenges and Opportunists**

(दिसम्बर 18-19, 2024)



प्रायोजक
उत्तरी क्षेत्रीय केन्द्र
भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान परिषद्, नई दिल्ली



आयोजक
म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान
उज्जैन

राष्ट्रीय सेमिनार

भारत में सार्वजनिक नीति के समसामयिक सन्दर्भ : चुनौतियाँ एवं सम्भावनाएँ (दिसम्बर 18-19, 2024)



सार्वजनिक नीति कानूनों, विनियमों और कार्यवाहियों का ढाँचा है जिसे सरकार सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लागू करती है। सार्वजनिक नीति सरकारी अधिकारियों और एजेंसियों के निर्णयों को आकार देती है, और यह समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति को प्रभावित करती है। इसमें आर्थिक, सामाजिक कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और पर्यावरण नीतियों सहित विभिन्न मुद्दे सम्मिलित होते हैं। राजनीतिक विचारधाराएँ, सामाजिक मूल्य और आर्थिक स्थितियाँ सार्वजनिक नीति को प्रभावित करती हैं, जो देश के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण हैं। समाजों को आकार देने और सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने में सार्वजनिक नीति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

वर्तमान में सार्वजनिक नीति का फलक बहुत बड़ा हो गया है और इसमें कई महत्वपूर्ण क्षेत्र – आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना, राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखना और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों तक के विषय प्रमुखता से समाहित होते

हैं। सार्वजनिक नीति समाज को आकार देने और व्यक्तियों के जीवन को बेहतर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा से लेकर पर्यावरण और सामाजिक कल्याण तक प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करती है। प्रभावी सार्वजनिक नीति संसाधनों के समान आवंटन को सुनिश्चित करती है, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है और सामाजिक चुनौतियों का समाधान करती है। सार्वजनिक नीति अधिक समावेशी और समृद्ध समाज बनाने के लिए उत्प्रेरक की तरह होती है। भारत में सार्वजनिक नीति का विकास विभिन्न कारकों से प्रभावित रहा है, जैसे – उपनिवेशवाद की विरासत, भारतीय समाज की विविधता और जटिलता, लोगों की आकांक्षाएँ और अपेक्षाएँ। भारत में सार्वजनिक नीति के विषय विविध और गतिशील रहे हैं, जिनमें राष्ट्र निर्माण, विकास और सुरक्षा के मुख्य मुद्दे शामिल हैं। भारत में सार्वजनिक नीति निर्माण की विशेषता निरन्तरता और परिवर्तन, आम सहमति और संघर्ष, केन्द्रीकरण और विकेन्द्रीकरण, तथा भागीदारी और बहिष्कार का मिश्रण रही है।

समय के साथ, भारत में सार्वजनिक नीति, उभरती चुनौतियों और अवसरों को सम्बोधित करने के लिए विकसित हुई है। वर्तमान एवं विगत कुछ वर्षों में विभिन्न विभागों के लिए सिटीजन चार्टर, वित्तीय समावेशन और प्रत्यक्ष लाभ कर, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), डिजिटल प्रमाणीकरण, मन्त्रालयों और विभागों का विलय एवं पुनर्विन्यास, सामाजिक समावेशन और कल्याण कार्यक्रम, महिला सशक्तीकरण और लैंगिक समानता, शिक्षा एवं कौशल विकास, सरकार एवं नागरिक परस्पर गतिशीलता, कृषि सहायता, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे क्षेत्रों में नीतियाँ एवं इनसे सम्बन्धित कार्यक्रम लागू किए गए हैं जो डिजिटल और विनिर्माण महाशक्ति बनने की देश की बढ़ती महत्वाकांक्षा को दर्शाती हैं।

भारत में सार्वजनिक नीति का नागरिकों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जो आर्थिक अवसरों से लेकर सामाजिक मानदंडों तक को आकार देती है। अच्छी सार्वजनिक नीति से गरीबी में कमी, स्वास्थ्य परिणामों में सुधार और शिक्षा तक पहुँच में वृद्धि जैसे सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। भारत में सार्वजनिक नीति का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव देश की आर्थिक वृद्धि और विकास पर पड़ता है। उदारीकरण और निजीकरण जैसी नीतियों ने तेजी से आर्थिक विस्तार किया है, जिससे व्यवसायों और व्यक्तियों दोनों के लिए नये अवसर पैदा हुए हैं।

भारत में सार्वजनिक नीति देश के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो बहुसंख्यक नागरिकों के जीवन को प्रभावित करती है। आर्थिक नीतियों से लेकर विकास को बढ़ावा देने वाली सामाजिक नीतियों तक जो कमजोर वर्गों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करना चाहती हैं, सार्वजनिक नीति के दूरगामी परिणाम होते हैं। इन्हीं तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, उज्जैन द्वारा 'भारत में सार्वजनिक नीति के समसामयिक सन्दर्भ : चुनौतियाँ एवं सम्भावनाएँ' विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन दिनांक 18 एवं 19 दिसम्बर, 2024 को किया जा रहा है।

सेमिनार के प्रस्तावित उपशीर्षक

- सार्वजनिक नीतियाँ – सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य
(Public Policies - Theoretical Perspective)
- भारत में सार्वजनिक नीति का इतिहास और विकास
(History and Development of Public Policy in India)
- भारतीय संविधान में सार्वजनिक नीति के लिए निहितार्थ
(Implications for Public Policy in the Indian Constitution)
- भारत में सार्वजनिक नीति निर्माण की प्रक्रिया एवं अभिकरण : नीति आयोग
(Process and Agencies of Public Policy Making in India: NITI Aayog)
- भारत में नीति निर्माण में संस्थानों का योगदान : विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका
(Contribution of Institutions in Policy Making in India: Legislature, Executive and Judiciary)
- भारत में सार्वजनिक नीतियों का क्रियान्वयन एवं विकेन्द्रीकरण
(Implementation of Public Policies in India and Decentralisation)
- समकालीन भारत में प्रमुख सार्वजनिक नीतिगत पहल
(Major Public Policy Initiatives in Contemporary India)
- भारत में राज्यों के राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक आयाम और सार्वजनिक नीति
(Political, Social and Economic Dimensions and Public Policy in Indian States)
- विभिन्न क्षेत्रों में सुधार एवं सार्वजनिक नीतियाँ : सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी, डिजिटल इंडिया, शिक्षा एवं कौशल विकास, मेक इन इंडिया
(Sectoral Reforms and Public Policies: Public and Private Partnership, Digital India, Education and Skill Development, Make in India)
- सार्वजनिक नीति के उभरते नये क्षेत्र
(Emerging New Areas of Public Policy)

सेमिनार प्रस्तावित उपविषयों पर केन्द्रित होगा। सेमिनार के उपविषयों से सम्बन्धित मुद्दों पर संकाय सदस्यों, अनुसन्धानकर्ताओं और विकास कार्यकर्ताओं से शोधपत्र प्रस्तुति हेतु आमन्त्रित किए जाते हैं। सेमिनार में अध्यक्षताओं के व्यापक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु चयनित पत्र-प्रस्तोताओं को प्रतिभागिता हेतु आमन्त्रित किया जायेगा। सेमिनार में प्रतिभागिता हेतु यात्रा-व्यय, आवास तथा अन्य सुविधाओं का प्रबन्धन संस्थान द्वारा किया जायेगा।

संक्षेपिका 100 से 150 शब्द तथा शोध पत्र 4000 से 5000 शब्द

भेजने की अन्तिम तिथि : 22 नवम्बर, 2024

ई-मेल : mailboxmpissr@gmail.com

डॉ. मनीष ज्ञानी
समन्वयक
9887279934

डॉ. आशीष भट्ट
संयोजक

प्रोफेसर यतीन्द्रसिंह सिसोदिया
निदेशक



म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान

(भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान संस्थान, शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार का स्वायत्त संस्थान)
6, प्रोफेसर रामसखा गौतम मार्ग, भरतपुरी प्रशासनिक प्रक्षेत्र, उज्जैन (म.प्र.) - 456010
फोन : 0734-2510978 ● ईमेल : mpissr@yahoo.co.in ● वेब : www.mpissr.org